

गुस्ताखी माफ

RNI NO PUNBIL/2014/59416

UTURNTIME.COM

आका नेतागण सभी, हम तो सिर्फ गुलाम।
जो-जो वे आदेश दें, करने पड़ते काम।
करने पड़ते काम, हमें तो भैया सारे।
हो कैसे इंकार, बॉस हैं वही हमारे।
कह साहिल कविराय, यही खाकी का खाका।
हम हैं सिर्फ गुलाम, हमारा नेता आका।



- डॉ. राजेन्द्र साहिल

यूटर्न टाइम्स

The Good, Bad and Ugly of India

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS



VOL: 11 | ISSUE 148 | MONDAY 08-06-2026 | RS-03 | PAGE-12 | PUBLISHED BY: LUDHIANA | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

जब जीतो महिला समर वेकेशन ने उड़ाए 50 नामी घरानों के होश

हाईटेक जापान के किस्से ने बढ़ा दी पंजाब के धन्ना सेटों की धड़कनें

लुधियाना/यूटर्न/07 जून। गर्मियों की छुट्टियां बिताने निकला एक लग्जरी विदेशी टूर अचानक ऐसा मोड़ लेगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। चर्चा है कि लुधियाना सहित पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों के करीब 50-60 धन्ना सेट परिवारों की महिलाएं इन दिनों जीतो महिला विंग के समर वेकेशन टूर पर विदेश गई हुई हैं। लेकिन जापान के एक बड़े स्टोर में घटी एक घटना ने कुछ घंटों के लिए भारत में बैठे कई नामी उद्योगपतियों और कारोबारियों की नींद उड़ा दी। सूत्रों के अनुसार, खरीदारी के दौरान एक महिला द्वारा देखा गया एक उत्पाद कथित तौर पर अपनी निर्धारित जगह के बजाय किसी अन्य शेल्फ पर रख दिया गया। कुछ देर बाद स्टोर प्रबंधन को वह उत्पाद अपनी जगह पर नहीं मिला तो सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। देखते ही देखते पूरे स्टोर को सील कर दिया गया और सभी ग्राहकों से पूछताछ शुरू हो गई।

बताया जाता है कि करीब तीन से चार घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान विदेशी धरती पर फंसी महिलाओं ने अपने धन्ना सेट परिवारों को सूचना दी। इसके बाद लुधियाना, दिल्ली और अन्य शहरों में बैठे कई प्रभावशाली परिवारों के फोन लगातार बजते रहे। चर्चा तो यहां तक है कि कारोबारी जगत से जुड़े लोगों ने अपने संपर्कों के जरिए जापान में विभिन्न



स्तरो पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। आखिरकार घंटों की तलाश के बाद कथित तौर पर वह उत्पाद दूसरे सामान के बीच रखा मिला और मामला शांत हो गया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। दुनिया जिस जापान को हाईटेक सिस्टम, स्मार्ट सर्विलांस और अनुशासित कार्यप्रणाली का उदाहरण

मानती है, वहां एक साधारण उत्पाद की खोज में कई घंटे लगना चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का मानना है कि सीसीटीवी और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम के दौर में ऐसी जांच कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती थी। फिलहाल यह घटना लुधियाना के कारोबारी और सामाजिक हलकों में चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है, जहां लोग इसे समर वेकेशन का सबसे महंगा तनाव बताकर चटकारे ले रहे हैं।

घरेलू गैस सिलेंडर 29 महंगा, आम परिवारों की रसोई पर बढ़ेगा बोझ

महंगाई की मार, सोचें समझकर करें इस्तेमाल



लुधियाना/यूटर्न/07 जून। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें लागू होने के बाद सिलेंडर की कीमत 940 से बढ़कर 969 हो गई है। संशोधित कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। गैस एजेंसियों के अनुसार यह बढ़ोतरी तेल कंपनियों द्वारा की गई मूल्य समीक्षा के बाद लागू की गई है। घरेलू सिलेंडर के अलावा 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर की कीमत 857.50 तथा 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,196 निर्धारित की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा। एक सामान्य परिवार हर महीने एक से दो सिलेंडर की खपत करता है। ऐसे में सालाना घरेलू बजट पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। पहले से ही खाद्य पदार्थों, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी चिंता का विषय बन सकती है। उपभोक्ताओं का कहना है कि रसोई गैस अब घरेलू जरूरत की अनिवार्य वस्तु बन चुकी है, इसलिए कीमतों में बार-बार होने वाली वृद्धि से मासिक खर्चों का संतुलन बिगड़ रहा है। लोगों ने सरकार और तेल कंपनियों से आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत देने की मांग की है।

फैक्ट बॉक्स

पुरानी कीमत :	940	नई कीमत :	969
बढ़ोतरी :	29 प्रति सिलेंडर		
5 किलोग्राम सिलेंडर :	857.50		
19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर :	3,196		
नई दरें :	तत्काल प्रभाव से लागू		

661 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़-पंचकुला समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी

अजीत झा
चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। हरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी विभागों से जुड़े 661 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली-एनसीआर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जांच एजेंसी ने छह विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में लिए। सीबीआई के अनुसार, जांच का केंद्र हरियाणा सरकार के आठ विभागों तथा चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों से जुड़े सरकारी फंड हैं। आरोप है कि सरकारी



धन को बैंक खातों के माध्यम से अनियमित तरीके से स्थानांतरित कर उसका दुरुपयोग किया गया।

जांच एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान हरियाणा कैडर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और एक निजी कंपनी से जुड़े परिसरों में चलाया

गया। नोएडा स्थित वीपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशक के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि

कुछ सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मियों ने कथित रूप से मिलकर खातों के संचालन, सरकारी धन के हस्तांतरण और उसे अन्य खातों में भेजने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इन लेन-देन के बदले संबंधित व्यक्तियों को कोई अनुचित लाभ तो नहीं मिला। एजेंसी के अनुसार, कथित घोटाले की राशि का एक हिस्सा वीपम कंसल्टेंसी के बैंक खाते में पहुंचा था, जहां से बाद में धनराशि को कंपनी निदेशक के निजी खाते में ट्रांसफर किए जाने के आरोप हैं। इसी पहलू को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। यह मामला

मूल रूप से हरियाणा विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो और चंडीगढ़ पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज मामलों से जुड़ा है। बाद में सीबीआई ने इन मामलों को अपने हाथ में लेकर व्यापक जांच शुरू की। तीनों मामलों में आपराधिक साजिश, सरकारी धन के गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है। सीबीआई इससे पहले पंचकुला की विशेष अदालत में इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में कुछ सरकारी विभागों के अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है।



02 सोमवार, 08 जून 2026

व्यापार/अन्य

यूटर्न टाइम
The Good, Bad and Ugly of India

ललित मोदी की बेबाक बातें: दाऊद की धमकी, सुनंदा पुष्कर विवाद, और कैसे तेंदुलकर-द्रविड़ ने पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था

ललित मोदी जितने लोगों को आकर्षित करते हैं और पसंद किए जाते हैं, उतने ही विवादों में भी घिरे रहते हैं। उनके चाहने वालों के लिए, वे एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) बनाई और क्रिकेट को अरबों डॉलर का ग्लोबल इवेंट बना दिया। वहीं, उनके आलोचकों के लिए वे आरोपों, जांच और अनसुलझे सवालों से घिरे व्यक्ति हैं।

एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ एक लंबी बातचीत में, मोदी ने IPL की शुरूआत, भारत से बाहर बिताए अपने सालों, राजनीति से अपने रिश्तों, कोच्चि IPL विवाद से जुड़े आरोपों और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियां मिलने के दावों पर बात की।

नीचे दिया गया लेख बातचीत में मोदी द्वारा उठाए गए मुद्दों और दावों पर आधारित एक इंटरव्यू है। इसमें बताए गए आरोप ललित मोदी के दावे हैं।

जब इतिहास ललित मोदी को याद करेगा, तो आपको क्या लगता है कि लोग उन्हें किस रूप में याद रखेंगे?

मुझे लगता है कि इतिहास मुझे उस व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग मुझे नापसंद कर सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं, मुझे विवादित कह सकते हैं, लेकिन कोई भी IPL के अस्सर से इनकार नहीं कर सकता। IPL से पहले, क्रिकेट काफी हद तक द्विपक्षीय सीरीज और पारंपरिक फॉर्मेट पर निर्भर था। हमने कुछ बिल्कुल अलग बनाया।

IPL सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं था। यह मनोरंजन, ब्रांडकास्टिंग, मार्केटिंग, शहर-आधारित वफादारी और एक ऐसा स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाने के बारे में था जो दुनिया की बेहतरीन लीगों से मुकाबला कर सके। आज हर कोई फ्रैंचाइजी लीग की बात करता है। जब हमने शुरूआत की थी, तो लोग हँसे थे। उन्होंने कहा था कि यह फेल हो जाएगा। अब देखिए यह कहाँ पहुँच गया है।

आपके इंटरव्यू का एक सबसे चर्चित हिस्सा दाऊद इब्राहिम से जुड़ी धमकियां मिलने का आपका आरोप है।



लोग दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही तुरंत सोचते हैं कि कोई कहानी बना रहा है। मैं बस वही बता सकता हूँ जो मैंने अनुभव किया। उस समय क्रिकेट एक बहुत बड़ा बिजनेस था। जहाँ भी बहुत पैसा होता है, वहाँ हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो प्रभाव जमाना चाहते हैं। सट्टेबाजी से जुड़े हित मौजूद थे। अपराधिक तत्वों ने शामिल होने की कोशिश की। यह कोई रहस्य नहीं था।

मुझे याद है कि मुझे बताया गया था कि एक जरूरी कॉल आया है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने अपनी पहचान दाऊद इब्राहिम के तौर पर बताई। शुरू में, मुझे लगा कि यह कोई मजाक हो सकता है। लेकिन बातचीत आगे बढ़ी और साफ हो गया कि यह कोई ऐसा-वैसा व्यक्ति नहीं था जो किसी और का नाटक कर रहा हो। मैं तो डर के मारे लगभग पैट में ही पेशाब कर बैठा था। मैसेज दोस्ताना नहीं था। मैसेज का मकसद यह बताना था कि कुछ लोग लिए जा रहे फैसलों से खुश नहीं थे। चेतावनियाँ थीं। ऐसे संकेत थे कि मुझे ज्यादा सहयोग करना चाहिए।

लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं डरा हुआ था। जाहिर है, मैं डरा हुआ था। कोई भी डर जाता। मेरा परिवार था। मेरी ज़िम्मेदारियाँ थीं। जब ऐसी साख वाला कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, तो आप तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ जाते हैं।

आपने कोच्चि IPL विवाद और शशि

थरूर को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

उस घटना ने कई लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। मैं कोच्चि फ्रैंचाइजी से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा था। IPL कमिश्नर के तौर पर मेरा काम यह समझना था कि किसका क्या मालिकाना हक है। ये कोई छोटे-मोटे निवेश नहीं थे। इनमें करोड़ों डॉलर शामिल थे। जब मैंने इसके स्ट्रक्चर को देखा, तो एक नाम बार-बार सामने आ रहा था: सुनंदा पुष्कर।

स्वाभाविक है, मैंने सवाल पूछे। बिजनेस में, अगर किसी को बड़ा हिस्सा मिल रहा है, तो उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बना रहा था। मैं अपना काम कर रहा था। मुझे जितना याद है, मुझे शशि थरूर का फोन आया था। उस समय वे एक प्रभावशाली मंत्री थे। मैसेज, जैसा कि मुझे याद है, बहुत साफ था। मुझसे कहा गया कि मैं सुनंदा पुष्कर से जुड़े सवालों को आगे न बढ़ाऊँ। मैंने पूछा क्यों।

जवाब, मेरे हिसाब से, यह था कि अगर मैंने ऐसा करना जारी रखा, तो मुझ पर छापे पड़ सकते हैं और गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर लोगों के साथ काम करते हुए बिताई है। मैं डरने या दबने को तैयार नहीं था। मुझे याद है मैंने सोचा था: अगर मालिकाना हक के स्ट्रक्चर के बारे

में सवाल पूछना गलत है, तो आखिर मेरा रोल क्या है? अगले दिन यह विवाद पूरे देश में फैल गया।

क्या आपको लगता है कि सुनंदा पुष्कर एक बहुत बड़े विवाद का चेहरा बन गई थीं?

बिल्कुल। मैंने यह कई बार कहा है। लोगों की बातचीत लगभग पूरी तरह से सुनंदा पुष्कर पर केंद्रित हो गई थी। लेकिन मेरा हमेशा से मानना था कि इसमें बड़े मुद्दे और बड़े हित शामिल थे। मीडिया ने हस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि हस्तियाँ सुर्खियाँ बनाती हैं। मालिकाना हक, प्रभाव और पारदर्शिता जैसे बुनियादी सवालों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। सुनंदा के बारे में किसी की भी राय कुछ भी हो, सच्चाई यह है कि वह एक ऐसे तूफान का केंद्र बन गई जो तेजी से किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो गया।

आपने T20 को इतना बड़ा कैसे बनाया?

यह मुश्किल था। 2007 के T20 वर्ल्ड कप से पहले मैंने तेंदुलकर, द्रविड़ और गांगुली से वर्ल्ड कप खेलने का अनुरोध किया, बल्कि उनसे विनती की, और उन्होंने T20 को एक मजाक कहा। अब देखिए कि इस खेल ने क्रिकेट में कैसी क्रांति ला दी है।

आपके आलोचक कहते हैं कि आप अक्सर खुद को पीड़ित के तौर पर पेश करते हैं।

मैं खुद को पीड़ित नहीं मानता। पीड़ित चुपचाप बैठकर शिकायत करते हैं। मैंने मुकाबला किया। मुझे चुनिंदा मुद्दों पर नाराजगी से आपत्ति है। लोग मेरे खिलाफ आरोपों को बार-बार दोहराते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी मेरी उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। IPL मुझे आसानी से नहीं मिला था। इसे सालों की मेहनत से बनाया गया था। इसमें बहुत बड़े जोखिम शामिल थे। कोई भी उन जोखिमों को याद नहीं रखता क्योंकि सफलता ने आखिरकार सब कुछ स्वाभाविक बना दिया। सफलता कभी भी स्वाभाविक नहीं होती।

कई भारतीय अभी भी वही सवाल पूछते हैं: अगर आपको लगता है कि आप

निर्दोष हैं, तो भारत वापस क्यों नहीं आते?

क्योंकि सवाल में ही अपराध मान लिया गया है। मैं कभी छिपा नहीं। मैं खुलेआम रहता हूँ। मैं खुलेआम यात्रा करता हूँ। हर कोई जानता है कि मैं कहाँ हूँ। सालों से लोग कह रहे हैं कि मैं भाग रहा हूँ।

किस चीज से भाग रहा हूँ? अगर कोई सीधी कानूनी प्रक्रिया होती जो सब कुछ जल्दी सुलझा सकती, तो मामले बहुत पहले ही खत्म हो गए होते। इसके बजाय, मैं अक्सर धारणाओं की लड़ाई देखता हूँ। आज मेरी जिंदगी स्थिर है। मेरे बिजनेस हैं। दुनिया भर में मेरे हित हैं। मैं डर-डरकर दिन नहीं बिता रहा हूँ।

क्या आपको कोई पछतावा है?

बिल्कुल। जो कोई भी कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, वह या तो झूठ बोल रहा है या उसमें आत्म-जागरूकता की कमी है। मैंने कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मान लिया कि वफादारी वहाँ मौजूद थी जहाँ वह नहीं थी। मेरा मानना था कि सफलता से सद्भावना मिलेगी। असल में, कामयाबी अक्सर जलन की वजह बनती है। लेकिन क्या मुझे कहना शुरू करने का कोई पछतावा है? कभी नहीं। एक पल के लिए भी नहीं।

आप चाहेंगे कि लोग आपको किस तरह याद रखें?

एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने कुछ ऐसा सोचा जो पहले कभी नहीं था और फिर उसे हकीकत में बदला। लोग मुझे निजी तौर पर पसंद करते हैं या नहीं, यह मायने नहीं रखता। आज IPL दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में से एक है। लाखों लोग इसे देखते हैं। हजारों लोगों ने इसकी वजह से अपना करियर बनाया है। इसकी वजह से क्रिकेट में बदलाव आया है। जब इतिहासकार इस दौर का विश्लेषण करेंगे, तो मुझे लगता है कि वे शोर-शराबे और असल कामयाबी के बीच फर्क कर पाएंगे। और जब वे ऐसा करेंगे, तो वे मानेंगे कि ललित मोदी के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाए, उन्होंने क्रिकेट के बिजनेस को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल दिया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर नेस्ले इंडिया ने दोहराई सस्टेनेबिलिटी की प्रतिबद्धता



चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेस्ले इंडिया ने जलवायु संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत कृषि और सर्कुलर इकोनॉमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कंपनी ने बताया कि उसने वर्ष 2018 की तुलना में प्रति टन उत्पाद निर्माण पर रूइन्स-1 और Scope-2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 70 प्रतिशत की कमी

हासिल की है। साथ ही ऊर्जा उपयोग में 13 प्रतिशत और पानी की खपत में 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

नेस्ले इंडिया की सभी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों अब 100 प्रतिशत नवीकरणीय बिजली पर संचालित हो रही हैं। कंपनी ने मोगा, नंजनगुड और साणंद संयंत्रों में बायोमास बायोलर स्थापित कर स्वच्छ ईंधन के

उपयोग को भी बढ़ावा दिया है।

कंपनी देशभर में लगभग 80 हजार डेयरी किसानों के साथ मिलकर कम-उत्सर्जन वाली खेती और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं, NESCAFÉ Plan के तहत 5 हजार से अधिक कॉफी किसानों को सतत कृषि और आजीविका सुधार से जोड़ा गया है। MAGGI Spice Plan के

माध्यम से मसाला उत्पादन में गुणवत्ता और पुनर्जोर्जी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा में करीब 200 बड़े और 5,800 से अधिक छोटे बायोडाइजेस्टर्स स्थापित किए गए हैं, जो गोबर को स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद में बदलकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं।





पेज 06 जीत के बाद पार्षद राजिंदर राजा ने किया शुक्राना...

हलवारा से दिल्ली
— अब सफर हुआ आसान!
पंजाब का नया एयर कनेक्टिविटी हब!

अगले आप भी हो सकते हैं ?

आप भी बनिए इस सफर का हिस्सा!
हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली की अपनी ट्रेवल फोटो शेयर करें और जीतें आकर्षक लक्की गिफ्ट

GIFTING PARTNER
RUCHIN JEWELLERS

नशा-मुक्ति का लुधियाना मॉडल पूरे पंजाब के लिए मिसाल: राज्यपाल कटारिया

‘अगर पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाना है तो सतगुरु राम सिंह की सोच और संस्कारों को अपनाना होगा’



लुधियाना, 7 जून। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून और पुलिस कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज में नैतिक जागरूकता, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब को वास्तव में नशा-मुक्त बनाना है तो संत सतगुरु राम सिंह द्वारा दिखाए गए संयम, अनुशासन और समाज सुधार के मार्ग को अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लुधियाना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सतगुरु राम सिंह ने डेढ़ शताब्दी पहले ही नशे, सामाजिक कुरीतियों और बुराईयों के खिलाफ जनजागरण का अभियान चलाया था। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी उस समय थीं। उन्होंने कहा कि जिस समाज में युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, वही समाज प्रगति के नए आयाम स्थापित करता है।

कटारिया ने कहा कि पंजाब की पहचान कभी मेहनत, खेती, उद्यम और वीरता से होती थी, लेकिन नशे की चुनौती ने इस गौरवशाली छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि सरकार, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, शिक्षण संस्थान और परिवार मिलकर नशे के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा करें। उन्होंने लुधियाना में चल रहे नशा जागरूकता अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि यह मॉडल पूरे पंजाब के लिए प्रेरणा बन सकता है। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूरी बनाकर अपने सपनों, परिवार और समाज के उज्वल भविष्य के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है।

सरकार की नीतियों से टूट रहा उद्योगों का भरोसा, पंजाब की इंडस्ट्री संकट में

उद्योगपति गुरमीत सिंह कुलार बोले— एक नोटिफिकेशन से खत्म हो जाती है वर्षों की मेहनत, बिजली कटौती और बढ़ते शुल्कों ने बढ़ाई चिंता

लुधियाना/ 05 जून। पंजाब की औद्योगिक नीतियों को लेकर उद्योग जगत में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। जाने-माने उद्योगपति गुरमीत सिंह कुलार ने सरकार की हालिया नीतियों और नोटिफिकेशनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उद्योगपतियों का सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने वाला व्यक्ति करोड़ों रुपये निवेश करता है, लेकिन एक सरकारी नोटिफिकेशन उसकी पूरी योजना को पल भर में बदल देता है। आईडीएफ (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) को बंद करने के फैसले को उन्होंने उद्योगों के लिए बड़ा झटका बताया। उनके मुताबिक यह कोई अनुदान नहीं, बल्कि नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम था।

नए शुल्कों ने बढ़ाई मुश्किलें



बिजली कटौती से उद्योग बेहाल

गुरमीत सिंह कुलार ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के लगने वाले बिजली कट उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्पादन रुकता है, जनरेटर चलाने पड़ते हैं और लागत बढ़ जाती है। उन्होंने सरकार से 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने पीएसआईसी द्वारा औद्योगिक प्लॉटों पर लगाए गए नए शुल्कों और रफ्ट फीस का भी विरोध किया। कुलार ने कहा कि उद्योग लगाने से पहले ही लाखों रुपये जमा करवाने की शर्त निवेशकों को हतोत्साहित कर रही है।

‘एक हाथ से राहत, दूसरे हाथ से वसूली’

कुलार ने कहा कि सरकार बिजली दरों में कटौती का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ सब्सिडी कम कर उद्योगों से ज्यादा पैसा वसूल लिया जाता है। उन्होंने इसे एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस लेना करार दिया।

पंजाब की रैंकिंग लगातार फिसली

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कभी पंजाब देश में कारोबार करने के लिए सबसे बेहतर राज्यों में शामिल था, लेकिन आज राज्य की रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है। अगर यही हाल रहा तो निवेशक दूसरे राज्यों का रुख कर सकते हैं।

पंजाब के उद्योगपतियों पर भरोसा करे सरकार

कुलार ने कहा कि पंजाब की पहचान साइकिल, सिलाई मशीन, कृषि उपकरण और ट्रेक्टर उद्योगों से रही है। सरकार को बाहरी निवेशकों के पीछे भागने की बजाय स्थानीय उद्योगपतियों को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगों में अपार क्षमता है और उन्हें सही माहौल मिले तो वे राज्य को फिर से औद्योगिक विकास के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उद्योगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर रोजगार, निवेश और पंजाब की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देगा।

GST घोटाले का महाविस्फोट : 9 कंपनियों पर केस, पुलिस और कर विभाग की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

फर्जी दस्तावेजों से GST नंबर, नकली बिलिंग के जरिए ITC का खेल



लुधियाना/यूटर्न/07 जून। पंजाब में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था को चूना लगाने वाले एक बड़े कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आबकारी एवं कराधान विभाग की शिकायतों पर लुधियाना पुलिस ने नौ कंपनियों और उनके संचालकों के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। आरोप है कि इन फर्मों ने जाली दस्तावेजों, गलत पहचान और फर्जी कारोबारी रिकॉर्ड के आधार पर GST पंजीकरण हासिल कर करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ कंपनियां केवल कागजों में संचालित हो रही थीं, जबकि उनके नाम पर बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री और वित्तीय लेन-

देन दर्शाए गए। जांच एजेंसियों को संदेह है कि फर्जी बिलिंग और ITC क्लेम का यह नेटवर्क कई अन्य फर्मों तक फैला हो सकता है। इसी कारण पुलिस और कराधान विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें अल्का ट्रेडिंग कंपनी, सैको इंडस्ट्रीज, पूजा एंटरप्राइजेज, श्री राधे ट्रेडिंग कंपनी, सितम एंटरप्राइजेज, गणपति पैकर्स इंडस्ट्रीज, बेनीपाल इंडस्ट्रीज, कृष्णा ट्रेडर्स और खालसा एंटरप्राइजेज शामिल हैं। विभिन्न मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य में फर्जी GST नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। कई बैंक खातों,

क्या है ITC का खेल ?

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) GST व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इसमें कारोबारी खरीदें गए सामान पर दिए गए टैक्स को अपने देय टैक्स से समायोजित कर सकते हैं। आरोप है कि फर्जी फर्मों ने नकली बिलों के जरिए इसी व्यवस्था का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये का लाभ लिया।

एक नजर में कार्रवाई

- 9 कंपनियों और संचालकों पर FIR
- फर्जी GST रजिस्ट्रेशन का आरोप
- करोड़ों के ITC लाभ की जांच
- कई बैंक खातों और दस्तावेजों की पड़ताल
- और कंपनियों पर भी गिर सकती है जांच की गज सबसे बड़ा सवाल...क्या सिर्फ 9 कंपनियां या पूरा सिंडिकेट? जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी GST नंबर और नकली बिलिंग का यह खेल कुछ कंपनियों तक सीमित था या इसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क सक्रिय था।

मोबाइल नंबरों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम जांच के घेरे में आ सकते हैं।



04 सोमवार, 08 जून 2026

हरियाणा

यूटर्न टाइम

हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी पहुंचे देवी के कार्यालय, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

दिनेश मौदगिल

लुधियाना/यूटर्न/07 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष गुरदेव शर्मा देवी के कार्यालय में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डाक्टर सुभाष शर्मा व जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान के साथ पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की तथा पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर भी बल दिया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और उनके नेतृत्व की सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी योजनाओं तथा



विभिन्न जनहित के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष गुरदेव शर्मा देवी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यालय आगमन पर उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है और इससे संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। कार्यक्रम में भाजपा के उपाध्यक्ष मनीष चोपड़ा, नरेंद्र सिंह मल्ली, उपाध्यक्ष लक्की शर्मा, प्रेस

सचिव डा.सतीश कुमार, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि बत्रा, विक्की सहोता, सर्कल प्रधान राजीव शर्मा, दीपक जौहर, अमित मित्तल, हिमांशु कालड़ा, संजय खटक, अभिषेक शर्मा, सुरेंद्र शिंदा, विजय खटक, हिमानी शर्मा, निशा, राकेश सहोता, आर्यन, सूरज डावल, दीपक बामनिया बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अवैध रेहड़ी-फड़ी वालों पर नगर निगम की कार्रवाई, शहरभर में 115 चालान काटे

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। नगर निगम चंडीगढ़ ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण और अवैध स्ट्रीट वेंडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की।

अभियान के दौरान बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा जमाने वाले रेहड़ी-फड़ी संचालकों के खिलाफ चालान किए गए। नगर निगम की प्रवर्तन टीमों ने सेक्टर-11, 12, 19, 22, 37, 40, 41, मनीमाजरा और सेक्टर-13 सहित विभिन्न इलाकों में व्यापक जांच अभियान चलाया। अधिकारियों ने बाजारों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। दिनभर चले इस अभियान के दौरान कुल 115



चालान जारी किए गए। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखना, पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही को सुचारु बनाना तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखना है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध वेंडिंग और अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने सभी स्ट्रीट वेंडर्स से निर्धारित नियमों का पालन करने और केवल अधिकृत स्थानों पर ही कारोबार करने की अपील की है। नगर निगम का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत कब्जों से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि आम लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं।

गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर संगोष्ठी आयोजित

वित्तीय पारदर्शिता और अनुपालन पर विशेषज्ञों का मंथन



लुधियाना/यूटर्न/07 जून। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) की लुधियाना शाखा द्वारा लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) के तत्वावधान में गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग विषय पर एक ज्ञानवर्धक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनआईआरसी की अध्यक्ष सीए नव्या मल्होत्रा, उपाध्यक्ष सीए अजीत सिंह चंदेल, सचिव सीए हितेश गोयल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

संगोष्ठी के तकनीकी सत्र में सीए अचल जैन ने गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रारूपों एवं मार्गदर्शिका पर विस्तृत जानकारी दी, जबकि सीए निलेश खेमका ने लेखांकन मानकों के प्रभावों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने प्रतिभागियों को वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, गुणवत्ता और अनुपालन के महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ लुधियाना शाखा के सचिव सीए केशव गुप्ता के स्वागत संबोधन से हुआ। इसके बाद शाखा के उपाध्यक्ष सीए राकेश ग्रोवर तथा

अध्यक्ष सीए विकास गोयल ने अपने विचार रखे। संगोष्ठी में लुधियाना एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया और विभिन्न व्यावसायिक विषयों पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर शाखा के कोषाध्यक्ष सीए अरुण सिंह ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम पेशेवर ज्ञान को समृद्ध करने और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

धूरी से भाजपा का चुनावी बिगुल, नायब सैनी ने साधा पंजाब सरकार पर निशाना



धूरी/चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को धूरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुटकुलों से सिनेमा हॉल तो चल सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चल सकती। पंजाब की जनता अब झूठे वादों और खोखले आश्वासनों की राजनीति से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। सैनी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को रक्रांतिकारी नहीं, बल्कि भ्रांतिकारी बताने हुए कहा कि वे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे के खिलाफ जंग केवल विज्ञापनों तक सीमित है, जबकि धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर भी पंजाब सरकार को घेरा और कहा कि किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी तथा उचित मुआवजा देने के वादे पूरे नहीं किए गए। इसके विपरीत हरियाणा सरकार सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद और प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने पंजाब में डबल इंजन सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा ही प्रदेश को विकास, निवेश, रोजगार और सुशासन की नई दिशा दे सकती है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह दिल्ली सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।





नीति आयोग की बैठक में पंजाब की उपलब्धियों पर फोकस करेंगे मुख्यमंत्री मान

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। 11 जून को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पंजाब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रमुखता से रखेगी। मुख्यमंत्री ईंदरलाल टल्लर बैठक में राज्य की विकास योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हुए बदलावों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों का विकास और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि हाल के वर्षों में सरकारी स्कूलों की ओर विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया गया है।

कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार सिंचाई नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए किए गए कार्यों को उजागर करेगी। बंद पड़ी नहरों और जल



वितरण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के साथ किसानों को अधिक नहरी पानी उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया जाएगा। सरकार इन प्रयासों को जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की रणनीति के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्रमुखता से रखा जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में

सुविधाओं के उन्नयन और आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी भी दी जाएगी। बैठक के दौरान औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े कदमों का भी उल्लेख होने की संभावना है। राज्य सरकार उद्योगों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों को अपनी उपलब्धियों के रूप में सामने रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक को केंद्र और राज्यों के बीच विकास संबंधी मुद्दों पर संवाद का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। पंजाब सरकार का मानना है कि यह बैठक राज्य की विकास पहलों और प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी।

पंजाब यूनिवर्सिटी को जल्द मिलेगा नया कुलपति, 100 से अधिक आवेदनों में से 30 नाम चयनित

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। कुलपति पद के लिए प्राप्त 100 से अधिक आवेदनों की समीक्षा के बाद सर्च कमेटी ने करीब 30 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब इन नामों में से तीन से पांच उम्मीदवारों का अंतिम पैनल तैयार कर चांसलर को भेजा जाएगा, जिसके बाद नए कुलपति की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। जानकारी के अनुसार, कुलपति पद के लिए सबसे अधिक आवेदन पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और प्रोफेसर्स की ओर से प्राप्त हुए। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों के शिक्षाविदों और वरिष्ठ अकादमिक विशेषज्ञों ने भी आवेदन किया है।

चयन प्रक्रिया के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी को उस समय अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ा, जब कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक बार आवेदन जमा कर दिए। ऐसे मामलों की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन में अतिरिक्त समय लगा। मौजूदा कुलपति रेनु विग का नियमित कार्यकाल 28 मार्च को समाप्त हो गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें चार माह का विस्तार दिया गया था, जो जुलाई में समाप्त होने जा रहा है। इसी कारण नए कुलपति के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। नए कुलपति के चयन के लिए गठित तीन सदस्यीय सर्च कमेटी में सभी महिला सदस्य शामिल हैं। कमेटी की अध्यक्षता माधुरी कान्तकार कर रही हैं। उनके साथ Shashikala वंजरी और विभा टंडन सदस्य के रूप में चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रही हैं। विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सर्च कमेटी जल्द ही अंतिम पैनल तैयार कर चांसलर को सौंप सकती है। इसके बाद औपचारिक मंजूरी मिलने पर पंजाब यूनिवर्सिटी को नया कुलपति मिल जाएगा, जो आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक दिशा तय करेगा।



पत्नी के घर छोड़ने पर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद युवक ने की आत्महत्या

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब में रविवार को सामने आई दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक ओर पत्नी के घर छोड़कर जाने से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, वहीं दूसरी ओर गर्लफ्रेंड

से हुए विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पहली घटना में पारिवारिक विवाद से परेशान एक युवक अपनी पत्नी के घर छोड़कर जाने से आहत होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना

मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने-बुझाने और परिजनों की मदद से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस दौरान इलाके में लोगों की भीड़ जमा रही और कई घंटों तक अफरा-तफरी

का माहौल बना रहा। दूसरी घटना में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुए विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और मामले की जांच की जा रही है।

पहले 600 मीटर सड़क तो ठीक करें, फिर 45 हजार किलोमीटर की बात करें: पवन दीवान

लुधियाना/यूटर्न/07 जून। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहरी) एवं पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पवन दीवान ने मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के 45 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत संबंधी दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और नगर निगम जोन-डी कार्यालय को जोड़ने वाली करीब 600 मीटर लंबी सड़क तक दुरुस्त नहीं हो सकी, तब पूरे पंजाब में हजारों किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के दावे कैसे किए जा सकते हैं। दीवान ने कहा कि उक्त सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर पिछले तीन महीनों से लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्यों के बजाय केवल प्रचार और विज्ञापनों पर ध्यान दे रही है।

उन्होंने बताया कि 18 मार्च 2026 को नगर निगम आयुक्त को तीन पन्नों का मांग पत्र सौंपकर शहर, विशेषकर



लुधियाना पश्चिम क्षेत्र की कई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन 82 दिन बीतने के बावजूद किसी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। दीवान ने मानसून से पहले शहर में जलभराव और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नहरी पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद कई सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिससे लोगों को परेशानी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से दावों के बजाय जमीनी स्तर पर काम करने की मांग की।

कोर्ट परिसर की पार्किंग से बाइक चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

डेराबस्सी/यूटर्न/07 जून। जहां आम लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया चलती है, उसी कोर्ट परिसर में वाहन चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डेराबस्सी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग से एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एसआई अमरजीत सिंह के अनुसार शिकायतकर्ता सुनील कुमार निवासी हरमिलाप नगर फेज-1, बलटाना (जीरकपुर) ने पुलिस को बताया कि वह डेराबस्सी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चपरासी के पद पर कार्यरत है। तीन जून की सुबह वह अपनी बजाज सीटी-100 मोटरसाइकिल लेकर ड्यूटी पर आया था और वाहन को कोर्ट परिसर की पार्किंग में खड़ा किया था। दोपहर के समय जब वह पार्किंग में वापस पहुंचा तो उसकी मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। काफी तलाश करने के बावजूद वाहन का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। घटना के बाद कोर्ट परिसर में आने वाले कर्मचारियों और वकीलों के बीच भी सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि अदालत परिसर जैसी जगहों पर भी वाहन सुरक्षित नहीं हैं तो सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जरूरत है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चोरी करने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

मेयर की टिप्पणी के बहाने प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस, आर.के. गर्ग ने मांगी जवाबदेही

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। चंडीगढ़ के मेयर द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई बार 'चपरासी उनसे अधिक ताकतवर नजर आते हैं', पर सामाजिक कार्यकर्ता आर.के. गर्ग ने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी महज एक बयान नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों में व्याप्त कुछ पुरानी व्यवस्थागत समस्याओं की ओर संकेत करती है। आर.के. गर्ग का



कहना है कि शहर के कई सरकारी विभागों में लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि आम नागरिकों को अपने काम करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि फाइलों की प्रक्रिया, अधिकारियों तक पहुंच और कार्यों के निष्पादन को लेकर लोगों की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। गर्ग ने कहा कि अधिकांश कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हैं, लेकिन जहां लगातार शिकायतें मिलती हों, वहां प्रशासन को व्यवस्था की समीक्षा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके अनुसार, नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और सुगम प्रशासन उपलब्ध कराना किसी भी सरकारी तंत्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन को कर्मचारियों के लिए निश्चित कार्यकाल और नियमित स्थानांतरण नीति लागू करनी चाहिए। इसके साथ ही व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण, कार्यप्रणाली की निगरानी और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।





जन्म देने वाली माता को देव-तुल्य मान पिता को देव समझ - सन्त अश्वनी बेदी

लुधियाना/यूटर्न/07 जून। श्री राम शरणम, श्री राम पार्क के साप्ताहिक सत्संग में संत अश्वनी बेदी जी ने कहा, उपनिषद के द्वारा स्वामी सत्यानन्द जी महाराज हमें समझाते हैं कि जन्म देने वाली माता को देव-तुल्य मान। पिता को देव समझ। आचार्य को देव जान। अतिथि को देव-तुल्य मान। जितने निर्दोष उत्तम कर्म हैं, वे संवत करने चाहिए। दूसरे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जितने हमारे शुभाचरण हैं तुझे वे धारण करने उचित हैं। दूसरे, हमारे दोष नहीं अनुकरण में लाने चाहिए। श्री महाराज वेद पढ़ा कर साधकों को उपदेश देते हैं कि - तू सत्य ही बोल। मिथ्यावचन कभी न बोल। धर्म का आचरण कर। स्वाध्याय में न प्रमाद करना। आलस्य और कुव्यसन को प्रमाद कहा है। आलस्य स्वाध्याय करने में रुकावट न बने। अतएव



नाम का चिन्तन, नाम का जाप, नाम का कीर्तन साधक को बड़ी भावना और भक्ति से करते रहना उचित है और यह साधना संसार के लिये बड़ी कल्याण-कारिणी है।

सभा में श्री महेश मित्तल, उमा मित्तल, आदित्य थापर, पंकज भल्ला, अभिराम थापर, अनहद थापर, श्रुति थापर, सुदर्शन जैन, सुमन जैन, रूपाली जैन, शशि

भल्ला, रामेश्वर गुप्ता, राज गुप्ता, संयम भल्ला, साक्षी गंभीर, दीक्षा धवन, गुलाब राय, शशि गुप्ता, गौरव भक्कू व अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रूह से रूबरू



चारु नागपाल

युवाओं में संस्कारों की कमी क्यों आ रही है?

यह सत्य है कि आज के समय में भारतीय संस्कारों की झलक युवाओं में पहले जैसी गहराई से नहीं दिख रही। इसके कई सामाजिक और व्यक्तिगत कारण हैं। सबसे पहले, आधुनिक तकनीक और वैश्वीकरण का प्रभाव युवाओं पर गहरा पड़ रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के

माध्यम से वे पश्चिमी संस्कृति से अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिससे पारंपरिक मूल्यों की पकड़ ढीली हो रही है। दूसरा कारण है परिवारों में बदलता वातावरण। पहले संयुक्त परिवारों में बड़ों का साथ और उनके अनुभवों से संस्कार सहज रूप से मिल जाते थे। आज अधिकांश परिवार छोटे हो गए हैं, जिससे बच्चों और युवाओं को परंपराओं और रीति-रिवाजों को नजदीक से समझने का अवसर कम मिल पाता है। तीसरा, शिक्षा और करियर की प्रतिस्पर्धा ने भी युवाओं को परंपराओं से दूर किया है। वे सफलता और आधुनिकता को प्राथमिकता देते हुए अक्सर अपने संस्कारों को 'पुराने जमाने की बातें' समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त, फिल्मों और विज्ञापनों का भी बड़ा प्रभाव है, जो जीवनशैली को अधिक आधुनिक और स्टाइलिश रूप में दिखाते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कार युवाओं में कमजोर पड़ रहे हैं, परंतु यदि परिवार और समाज मिलकर बच्चों में बचपन से ही इन मूल्यों को रोपित करें, तो यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है।

कानूनी बात - निशांत प्रभाकर के साथ

क्या Divorce के बाद भी Husband-Wife एक ही घर में रह सकते हैं?

Divorce के बाद सामान्यतः पति-पत्नी अलग-अलग रहने लगते हैं, लेकिन कानून ऐसा कोई नियम नहीं बनाता कि तलाक के बाद एक ही घर में रहना पूरी तरह असंभव या illegal हो जाए। यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी practical, financial, parental या अन्य कारण से एक ही घर में रहना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

कई मामलों में बच्चों की पढ़ाई, financial limitations, joint property, या business commitments के कारण लोग कुछ समय तक साथ रहते हैं, भले ही उनका वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से समाप्त हो चुका हो। हालांकि, यह स्थिति भविष्य में कुछ कानूनी और practical complications भी पैदा कर सकती है—विशेष रूप से maintenance, custody, remarriage, या future disputes के संदर्भ में। यदि दोनों के बीच लगातार विवाद, harassment या violence हो, तो एक ही घर में रहना और अधिक कानूनी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।

अदालत सामान्यतः यह नहीं तय करती कि Divorce के बाद पक्षों को किस प्रकार रहना चाहिए, जब तक कि किसी specific order, residence dispute, या safety issue का प्रश्न न हो।

कई लोग यह मान लेते हैं कि Divorce के बाद साथ रहना अपने आप Divorce को invalid बना देगा, जबकि ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण बात दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति और परिस्थितियां हैं।

निष्कर्ष: Divorce के बाद भी कुछ परिस्थितियों में Husband और Wife एक ही घर में रह सकते हैं। यह illegal नहीं है, लेकिन भविष्य के कानूनी और व्यक्तिगत प्रभावों को समझना आवश्यक है।



निशांत प्रभाकर, एडवोकेट

जीत के बाद पार्षद राजिंदर राजा ने किया शुक्राना, विधायक रंधावा भी हुए नतमस्तक

जीरकपुर/यूटर्न/07 जून। जीरकपुर के चर्चित वार्ड नंबर 19 से नव निर्वाचित पार्षद राजिंदर सिंह राजा ने अपनी जीत के बाद परमात्मा का शुक्राना अदा करने के लिए पाठ और कीर्तन समागम करवाया। इस मौके पर हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने भी गुरुघर में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया और राजा को जीत की बधाई दी।

विधायक रंधावा ने कहा कि वार्डवासियों ने राजिंदर सिंह राजा की मेहनत, ईमानदार कार्यशैली और लंबे समय से की जा रही जनसेवा पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वार्ड में विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि नगर परिषद चुनावों के दौरान वार्ड नंबर 19 काफी चर्चा में रहा था। 29 मई को घोषित नतीजों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजिंदर सिंह राजा ने पूर्व विधायक



एनके शर्मा के भाई यादवींद्र शर्मा को 23 वोटों से हराया था। परिणामों के बाद डाटा एंट्री में हुई गलती को लेकर विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के

बाद राजा की जीत पर आधिकारिक मुहर लग गई। समागम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभी ने नव निर्वाचित पार्षद को बधाई दी।

अमृतसर में 5 लाख नकदी और 40 तोले सोने की लूट, जालंधर में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी सस्पेंड

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब में रविवार को कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जुड़े दो बड़े मामलों ने सुर्खियां बटोरीं। अमृतसर में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश करीब 5 लाख रुपये की नकदी और 40 तोले सोना लेकर फरार हो गए, जबकि जालंधर में रिश्वत लेने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया



गया। अमृतसर में हुई लूट की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात बदमाशों ने

सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया और नकदी व सोने के आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं जालंधर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने के आरोपों में एक पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

भारत सरकार का बड़ा फैसला: विदेशी निवेशकों (FIIs) के लिए सरकारी बॉन्ड्स अब पूरी तरह टैक्स-फ्री!

लुधियाना/यूटर्न/07 जून। टैक्स मामलों के एक्सपर्ट एडवोकेट करन चावला (B.Com., LL.B.) ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भारत सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला फैसला लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'द इनकम-टैक्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनंस, 2026' (आयकर संशोधन अध्यादेश, 2026) जारी किया गया है।

यह नया नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस तारीख के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले मुनाफे पर यह छूट मिलनी शुरू हो जाएगी।

इस नए नियम के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities या G-Secs) से होने वाली ब्याज आय और कैपिटल गेन्स (पूँजीगत लाभ) पर 100% टैक्स छूट दे दी गई है।

सरल शब्दों में कहें तो, अब विदेशी बड़े निवेशकों को भारत सरकार के बॉन्ड्स में पैसा लगाने पर मिलने वाले मुनाफे पर भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन एक आम आदमी

(Layman) के रूप में आपको यह सोचना चाहिए कि विदेशी निवेशकों को टैक्स छूट मिलने से मुझे क्या फायदा या नुकसान? आइए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं।

आम आदमी (Layman) के लिए इसके फायदे (Advantages) यद्यपि यह छूट सीधे तौर पर विदेशी कंपनियों को मिली है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष (Indirect) असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर बेहद सकारात्मक हो सकता है: सस्ते कर्ज की उम्मीद (लोन की एटक कम होना): जब विदेशी निवेशक भारत सरकार के बॉन्ड्स भारी मात्रा में खरीदेंगे, तो सरकार के लिए बाजार से उधार लेना सस्ता हो जाएगा। जब सरकारी बॉन्ड की यील्ड (ब्याज दर) कम होगी, तो बैंकों के लिए भी फंड्स की लागत घटेगी। इसका सीधा फायदा आम आदमी को होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की कम एटकके रूप में मिल सकता है।

मजबूत रुपया और कम महंगाई: इस साल 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से काफी पैसा निकाला है, जिससे रुपये पर दबाव था। अब टैक्स छूट मिलने से भारत में भारी मात्रा में डॉलर (विदेशी मुद्रा) वापस आएगा। विदेशी



मुद्रा भंडार बढ़ने से भारतीय रुपया मजबूत होगा। जब रुपया मजबूत होता है, तो कच्चे तेल (Petroleum) और अन्य आयातित सामानों की कीमत घटती है, जिससे देश में महंगाई कम होती है।

देश का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर: सरकार इन सरकारी बॉन्ड्स के जरिए जो पैसा जुटाती है, उसका इस्तेमाल हाईवे, रेलवे, अस्पताल, स्कूल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में किया जाता है। विदेशी पैसा आने से देश में विकास कार्य तेज होंगे, जिससे आम जनता का जीवन स्तर सुधरेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

आम आदमी (Layman) के लिए इसके नुकसान या चिंताएं (Disadvantages) हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस फैसले के कुछ ऐसे बारीक पहलू भी हैं जो आम आदमी की जेब या देश के आर्थिक संतुलन पर असर डाल सकते हैं: आम भारतीय निवेशकों के साथ असमानता: एक आम भारतीय नागरिक यदि सरकारी बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो उसे अपनी गाढ़ी कमाई के मुनाफे पर टैक्स (LTCG/STCG या स्लैब रेट के अनुसार) देना पड़ता है। वहीं विदेशी अरबपतियों के लिए इसे पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है। एक आम टैक्सपेयर के मन में यह सवाल उठ सकता है कि अपनों से टैक्स और बाहर वालों को पूरी छूट क्यों?

सरकारी राजस्व (Tax Revenue) का नुकसान: विदेशी निवेशकों से मिलने वाला टैक्स सरकार की कमाई का एक हिस्सा था। इस टैक्स को खत्म करने से सरकार के राजस्व में जो कमी आएगी, उसकी भरपाई सरकार को कहीं न कहीं अन्य टैक्सों (जैसे GST या अन्य डायरेक्ट टैक्स) के जरिए आम जनता की जेब से ही करनी पड़ सकती है।

विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता: यदि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशकों (FIIs) के भरोसे चलने लगेगा, तो वैश्विक स्तर पर किसी भी संकट (जैसे युद्ध या वैश्विक मंदी) के समय यदि ये निवेशक अचानक अपना पैसा खींचते हैं, तो भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में बड़ी अस्थिरता आ सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion) देखा जाए तो सरकार का यह कदम दवाई की उस कड़वी घूंट की तरह है, जो शॉर्ट-टर्म में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन लॉन्ग-टर्म में देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए जरूरी है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके सरकार देश को एक बड़ी वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने और रुपये को टूटने से बचाने का प्रयास कर रही है। एक आम आदमी के तौर पर, यदि इससे देश में बुनियादी ढांचा सुधरता है और आने वाले समय में ब्याज दरें कम होती हैं, तो यह फैसला अंततः देशहित में ही साबित होगा। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। नवीनतम नियमों की बारीकियों के लिए आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन को हमेशा प्राथमिकता दें।

मां की स्मृति में लगा दिलों को स्वस्थ रखने का शिविर, 160 लोगों ने उठाया लाभ

लुधियाना/यूटर्न/07 जून। बढ़ती हृदय रोग संबंधी समस्याओं और महंगे इलाज के दौर में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भगवान महावीर सेवा संस्थान एवं दीप हॉस्पिटल के सहयोग से हरगोविंद नगर स्थित गुप्ता क्लीनिक में विशाल निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर संस्थान की प्रेरणास्रोत एवं बैकबोन स्वर्गीय पूनम गुप्ता की स्मृति को समर्पित था।

शिविर में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनवीर सिंह खुराना (डीएम, दीप हॉस्पिटल) ने मरीजों की जांच की तथा हृदय रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता और समय पर जांच से हृदय संबंधी



गंभीर बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। शिविर में मरीजों के लिए निःशुल्क हृदय जांच, शुगर टेस्ट, रक्तचाप जांच, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और दवाइयों की व्यवस्था की गई थी। करीब 160 मरीजों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन और प्रबंधक डॉ. प्राण गुप्ता ने बताया कि स्वर्गीय पूनम गुप्ता के

पुत्र अद्भुत गुप्ता, जो अमेरिका में रहते हैं, हर वर्ष अपनी माता की स्मृति में समाजसेवा का कोई न कोई कार्य करवाते हैं।

उनका उद्देश्य ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इस अवसर पर डॉ. नेहा गुप्ता, डॉ. सुरेंद्र मदान, गोकुलेश गुप्ता सहित संस्थान के

कई पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक मौजूद रहे। संस्थान की ओर से जनसेवा और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. मनवीर सिंह खुराना को विशेष सम्मान से भी सम्मानित किया गया। संस्थान ने भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगातार आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लुधियाना में भाजपा नेताओं ने किया स्वागत



लुधियाना/यूटर्न/07 जून। भारतीय जनता पार्टी लुधियाना के अध्यक्ष रजनीश धीमान के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini के लुधियाना आगमन पर स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा लुधियाना की जनरल सेक्रेटरी डॉ. कनिका जिंदल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, जनहित के मुद्दों तथा क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। नेताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनता के हितों से जुड़े कार्यों को गति देने पर भी विचार-विमर्श किया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए विकास एवं सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिकता है और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय से विकास कार्यों को नई दिशा मिलती है। कार्यक्रम में सांसद एवं उद्योगपति Rajinder Gupta, भाजपा लुधियाना अध्यक्ष रजनीश धीमान, उपाध्यक्ष महेश दत्ता, जनरल सचिव मल्ली तथा यशपाल जनोत्रा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने इसे संगठनात्मक समन्वय, जनसेवा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

CBI ने 645 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में 3 IAS और 1 IFS अधिकारी के घरों पर छापेमारी की

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शनिवार को IDFC फर्स्ट बैंक और अव स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले के सिलसिले में हरियाणा कैडर के तीन कर्नल अधिकारियों और एक IFS अधिकारी के चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR स्थित घरों पर छापेमारी की।

CBI के मुताबिक, धोखाधड़ी की रकम 661 करोड़ रुपये है, जिसमें हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों का पैसा गलत तरीके से निकाला गया। हालांकि, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) का दावा है कि 645 करोड़ रुपये का गबन किया गया था।

जिन हरियाणा कैडर के IAS अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की गई, उनमें मोहम्मद शहीन, पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार शामिल हैं। उनसे टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। जब यह धोखाधड़ी हुई, तब शहीन हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के MD थे, अग्रवाल कृषि विभाग में प्रशासनिक सचिव के तौर पर काम कर रहे थे और प्रदीप कुमार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव थे।

IFS अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव



(जो चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी - CREST के पूर्व CEO थे) और एक प्राइवेट फर्म M/s विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड व उसके डायरेक्टर के यहां भी छापेमारी की गई।

कुल मिलाकर छह जगहों पर तलाशी ली गई। CBI ने एक बयान में कहा, जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाने, फंड ट्रांसफर करने और बाद में उसे दूसरी जगह भेजने में मदद की। आरोप है कि उन्हें इस मदद और कार्रवाई न करने के बदले अनुचित लाभ मिला। बयान में आगे कहा गया, पता चला है कि नोएडा स्थित M/s विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को अपने अकाउंट में अपराध से जुड़ी रकम मिली थी, जिसे बाद में

डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, प्रॉपर्टी के कागजात और अन्य जरूरी सामान जब्त किए गए। हरियाणा सरकार ने पहले ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत आठ IAS अधिकारियों की जांच की अनुमति दे दी थी। इनमें मोहम्मद शहीन, पंकज अग्रवाल, विनीत गर्ग, आरके सिंह, प्रदीप कुमार, मणि राम शर्मा और साकेत कुमार शामिल थे। आठवें अधिकारी कर्नल डीके बेहरा थे।

CBI ने पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी और उनके फोन भी जब्त किए थे। जब यह घोटाला सामने आया, तो हरियाणा सरकार ने दो IAS अधिकारियों, आर.के. सिंह और प्रदीप कुमार, को सस्पेंड कर दिया और बाकी अधिकारियों का तबादला कर दिया।

आरोप है कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में सरकारी विभागों के खाते IAS अधिकारियों के कहने पर खोले गए थे और संबंधित विभागों में उनके कार्यकाल के दौरान इन खातों से पैसे का गबन किया गया। CBI ने इस मामले में 8 अप्रैल को FIR दर्ज की।

मेरे नाम और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर मेजी गई फर्जी शिकायत की जांच हो: अरविंद सिंह

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद सिंह (हेलो माजरा) ने अपने नाम और मोबाइल नंबर का कथित रूप से दुरुपयोग कर चंडीगढ़ पुलिस को भेजी गई एक फर्जी शिकायत की जांच की



मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की एसपी को लिखित शिकायत सौंपकर दोषी व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अरविंद सिंह ने बताया कि उनकी जानकारी और अनुमति के बिना किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक शिकायत संबंधी ई-मेल में उनका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज

कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त शिकायत से उनका कोई संबंध नहीं था और न ही उन्होंने ऐसी कोई शिकायत पुलिस को भेजी थी।

उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर-34 में तैनात एएसआई बलकार सिंह द्वारा उनसे संपर्क किए जाने के बाद उन्हें इस मामले की जानकारी मिली। जांच के दौरान पता चला कि शिकायत किसी अन्य व्यक्ति की ई-मेल आईडी से भेजी गई थी, लेकिन उसमें उनका नाम और मोबाइल नंबर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। अरविंद सिंह ने कहा कि इस तरह किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करना गंभीर मामला है। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि प्रभावित हुई, बल्कि पुलिस प्रशासन का बहुमूल्य समय भी व्यर्थ हुआ। साथ ही उन्हें अनावश्यक पूछताछ और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि संबंधित ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नागरिक के नाम और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल कर प्रशासन और आम लोगों को परेशान न कर सके।

बम धमकी ई-मेल मामले में चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई, पश्चिम बंगाल का आरोपी रिमांड पर लेकर पूछताछ

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब सिविल सचिवालय, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा कई शिक्षण संस्थानों को बम धमकों की धमकी देने वाले ई-मेल मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी एक आरोपी से पूछताछ की है। आरोपी की पहचान सौरव बिस्वास के रूप में हुई है, जिसे तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर चंडीगढ़ लाया गया था। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच के अनुसार, पंजाब सिविल सचिवालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरा संदेश भेजा गया था। तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई। जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था और ई-मेल डेटा तथा फर्जी डिजिटल पहचान से जुड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी कथित रूप से वीपीएन और फर्जी ई-मेल आईडी का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाने में माहिर था। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या वह अन्य लोगों को भी ऐसी तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता था और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं।

पूछताछ के दौरान आरोपी से धमकी भरे ई-मेल भेजने के पीछे की मंशा और संभावित सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। पुलिस के अनुसार मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच अभी जारी है और डिजिटल उपकरणों तथा अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी पहले भी अन्य राज्यों की पुलिस एजेंसियों की जांच के दायरे में रह चुका है। उसे पहले गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में विभिन्न मामलों में पूछताछ के लिए अलग-अलग एजेंसियों ने प्रोडक्शन वारंट हासिल किए। चंडीगढ़ पुलिस भी इससे पहले एक अन्य मामले में उससे पूछताछ कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि बम धमकी जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि इससे सार्वजनिक संस्थानों में दहशत फैलती है और सुरक्षा एजेंसियों के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। मामले में आगे की जांच जारी है।

मनीमाजरा की समस्याओं को लेकर सांसद मनीष तिवारी से मिला प्रतिनिधिमंडल

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। मनीमाजरा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं समाजसेवी मनीष तिवारी से क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद इरफान ने किया।

प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर मनीमाजरा में लोगों को प्रभावित कर रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में बिजली आपूर्ति, बस सेवा, बच्चों के स्कूलों में दाखिले में आने वाली दिक्कतों, पार्कों में फैली गंदगी, आवारा कुत्तों की समस्या, सफाई व्यवस्था, कानून-व्यवस्था तथा पेयजल आपूर्ति से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता



से उठाया गया।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मनीमाजरा में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए प्रयासों पर सांसद मनीष तिवारी का आभार भी जताया। मोहम्मद इरफान ने उनसे आग्रह किया कि क्षेत्र की अन्य लंबित समस्याओं के समाधान के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश

दिए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। सांसद मनीष तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निवारण उनकी

प्राथमिकता है और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सांसद का धन्यवाद करते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। मोहम्मद इरफान ने कहा कि मनीष तिवारी हमेशा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद के प्रयासों और सहयोग से क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं, जिससे लोगों को लाभ मिला है और मनीमाजरा निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शमीम अहमद, परवेज अहमद सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पत्नी के घर छोड़ने पर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद युवक ने की आत्महत्या

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब में रविवार को सामने आई दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक ओर पत्नी के घर छोड़कर जाने से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, वहीं दूसरी ओर गर्लफ्रेंड से हुए विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पहली घटना में पारिवारिक विवाद से परेशान एक युवक अपनी पत्नी के घर छोड़कर जाने से आहत होकर मोबाइल

टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने-बुझाने और परिजनों की मदद से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस दौरान इलाके में लोगों की भीड़ जमा रही और कई घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। दूसरी घटना में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुए विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से कुछ

महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों घटनाओं ने मानसिक तनाव और रिश्तों में बढ़ती संवेदनशीलता को एक बार फिर उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भावनात्मक संकट की स्थिति में जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय परिवार, मित्रों या विशेषज्ञों की मदद लेना जरूरी है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।





घग्गर में फिर गूजा खनन का शोर, डी-सिल्टिंग की आड़ में रेत निकासी पर सवाल

घग्गर में फिर गूजा खनन का शोर, डी-सिल्टिंग की आड़ में रेत निकासी पर सवाल

डेराबस्सी/यूटर्न/07 जून। भांखरपुर के पास घग्गर नदी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर रेत निकासी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन और संबंधित विभाग जहां इसे डी-सिल्टिंग (नदी की सफाई) का कार्य बता रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि नदी में भारी मशीनों और टिपरों की मदद से 10 से 15 फीट तक गहरे गड्ढे बनाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर बहते पानी के नीचे से भी रेत निकाली जा रही है। उनका आरोप है कि जहां वास्तव में गाद जमा है, वहां कोई सफाई कार्य नहीं हो रहा, बल्कि केवल रेत वाले क्षेत्रों को ही निशाना बनाया जा रहा है।

लोगों का कहना है कि पिछली बार भी डी-सिल्टिंग के नाम पर सैकड़ों टिपर रेत निकाली गई थी। अब उस दौरान जमा किए गए रेत



के ढेरों को भी बाहर भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने दावा किया कि काम देर रात तक जारी रहता है, जबकि नियमानुसार निर्धारित समय के बाद इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि यह वास्तव में डी-सिल्टिंग है तो निकाली गई सामग्री को व्यावसायिक रूप से बाहर क्यों भेजा जा रहा है। इस संबंध में जब ड्रेनेज विभाग के

एसडीओ रमनजीत सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि कार्यालय आकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र में पूर्व में डी-सिल्टिंग के लिए ठेका दिया गया था। उस समय ठेकेदार कंपनी पर निर्धारित शुल्क जमा न करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। ऐसे में घग्गर में दोबारा शुरू हुई गतिविधियों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

उठ रहे ये बड़े सवाल

- डी-सिल्टिंग या माइनिंग? यदि नदी की सफाई हो रही है तो केवल रेत वाले हिस्सों में ही मशीनें क्यों चल रही हैं?
- रात में कैसे चल रहा काम? स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात तक मशीनें और टिपर सक्रिय रहते हैं।
- निकाली गई रेत कहां जा रही है? रेत को ट्रकों में भरकर बाहर भेजे जाने पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। कौन करेगा निगरानी? खनन, ड्रेनेज और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की जुबानी गुरमीत सिंह, ग्रामीण भांखरपुर 'नदी की सफाई के नाम पर केवल रेत निकाली जा रही है। जहां गाद जमा है, वहां कोई काम नहीं दिख रहा।' सुरिंदर कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता 'घग्गर में कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे बरसात के समय खतरा बढ़ सकता है।' जसविंदर सिंह, किसान

अपमान से पहचान तक: काँकरोच जनता पार्टी एक मजबूत प्रेशर ग्रुप; आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। कोर्टरूम में की गई एक विवादित टिप्पणी से शुरू हुई बात अब भारतीय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली राजनीतिक घटना बन गई है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके द्वारा शुरू किए गए व्यापक आंदोलन 'काँकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने 'काँकरोच' शब्द को अपमानजनक लेबल से बदलकर हजारों ऐसे युवा भारतीयों के लिए एक एकजुट होने का नारा बना दिया है, जो बेरोजगारी, परीक्षा से जुड़े विवादों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी से परेशान हैं।

यह आंदोलन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की उन टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ, जिनका मतलब कई लोगों ने कुछ बेरोजगार और राजनीतिक रूप से सक्रिय युवाओं की तुलना 'काँकरोच' और 'परजीवी' (पैरासाइट) से करने के तौर पर निकाला।

इसके बाद जो हुआ, वह दिपके की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। उखड़ ने गूगल फॉर्म के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा,



#MainBhiCockroach ('मैं भी काँकरोच हूँ') हैशटैग को लोकप्रिय बनाया और विपक्षी नेताओं, एक्टिविस्ट और मशहूर हस्तियों का समर्थन हासिल किया। सबसे पहले राजनीतिक समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिला, जिनका एक छोटा सा सोशल मीडिया पोस्ट — 'BJP बनाम CJP' — तेजी से वायरल हुआ और आंदोलन के मुख्य नारों में से एक बन गया। कई विपक्षी दलों के नेता इस ट्रेंड में शामिल हुए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिंसोदिया ने कहा, 'मैं भी काँकरोच हूँ,' और साथ ही कहा कि वह गर्व के साथ काँकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हैं;

उन्होंने इसे 'मगरमच्छ और काँकरोच' के बीच की लड़ाई बताया। महुआ मोडना और कीर्ति आजाद ने भी सार्वजनिक रूप से सदस्यता मांगी। आजाद ने मजाक में पूछा कि इसमें शामिल होने के लिए क्या योग्यता चाहिए। शायद सबसे अहम समर्थन एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधार के पैरोकार सोनम वांगचुक से मिला, जिन्होंने खुद को 'ऑनररी काँकरोच' (मानद काँकरोच) बताया। उन्होंने साफ किया कि वह 'न तो बेरोजगार हैं और न ही आलसी'।

यह आंदोलन अब हैशटैग से आगे बढ़ चुका है। हाल ही में सैकड़ों समर्थक जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए और शिक्षा व भर्ती से जुड़े मुद्दों पर

जवाबदेही की मांग की। उनमें 20 साल का सार्थक भी शामिल था, जिसने एक न्यूज एजेंसी को बताया, 'भारत सरकार से अहम परीक्षाओं के बेहतर संचालन का हकदार है।' आरुषि नाम की एक छात्रा, जिसने सिर्फ अपना पहला नाम बताया, ने कहा कि यह आंदोलन उस लेबल को वापस अपनाकर उसे नई पहचान देने के बारे में है, जिसे कई युवा अपमानजनक मानते थे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर सुखविंदर सिंह का मानना है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत चुनावी राजनीति के बजाय सार्वजनिक बहस को प्रभावित करने की क्षमता में है। उनके अनुसार, उखड़ एक तरह का प्रेशर ग्रुप है और उसे वैसा ही बने रहना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर यह एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी में बदल जाता है, तो इससे वह सहजता और नैतिक बल कमजोर हो सकता है, जिसने इसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है। अभी 'काँकरोच जनता पार्टी' कुछ हद तक किसान आंदोलन और अन्ना आंदोलन की झलक दिखाती है, लेकिन बहुत धुंधले तौर पर।

घटिया दहेज लाने के आरोप बाइक, गाड़ी और 5 लाख रुपये की मांग, पर्चा

—चरणजीत सिंह चन्न—

जगरांव/यूटर्न/7/जून। लुधियाना ग्रामीण पुलिस द्वारा साझा की गई क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, महिला थाने में दहेज से संबंधित शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर के मुताबिक, गांव संगोवाल, फिल्लौर निवासी निंदर सिंह की पुत्री गुरप्रीत कौर ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल पक्ष द्वारा उसे कथित तौर पर कम और घटिया दहेज लाने के लिए ताने दिए जाते थे। शिकायत के अनुसार, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज की गई। इसके अलावा, उन पर बाइक, गाड़ी और 5 लाख रुपये नकद लाने के लिए दबाव बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, शिकायत की जांच थाना प्रभारी द्वारा की गई। जांच के बाद माननीय एसएसपी, लुधियाना ग्रामीण के आदेशों के अनुसार हरविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

एक महीने से सीवरेज के गंदे पानी में डूबा प्रभात रोड मार्केट, व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बार-बार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं, सोमवार तक कार्रवाई न हुई तो सड़क जाम की तैयारी



जीरकपुर/यूटर्न/07 जून। शहर की प्रमुख व्यावसायिक मंडियों में शुमार प्रभात रोड मार्केट पिछले करीब एक महीने से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रही है। सड़क पर बह रहे गंदे पानी और बदबू के कारण दुकानदारों और ग्राहकों का यहां आना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में लगातार सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से न केवल कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, जिससे व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है।

स्थानीय व्यापारी जॉनी, जगजीत जगा, मिट्टू, मोनू गौड़, निशांत गोयल और डॉ. विनोद ने बताया कि पिछले एक महीने से नगर परिषद अधिकारियों को शिकायतें भेजी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि प्रभात रोड मार्केट जीरकपुर की सबसे पुरानी और व्यस्त मार्केटों में से एक है, फिर भी इसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले सप्ताह सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मामले की शिकायत मोहाली के उपायुक्त और सीएम विंडो पर भी दर्ज करवाई जाएगी। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सीवरेज व्यवस्था की तत्काल मरम्मत कर स्थायी समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और व्यापार सामान्य रूप से चल सके।

क्या बोले अधिकारी

'कल सुबह टीम भेजकर मौके की जांच करवाई जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा।' — सवनीत सिंह, जेई, नगर परिषद जीरकपुर





10 सोमवार, 08 जून 2026

चंडीगढ़

यूटर्न टाइम
The Good, Bad and Ugly of India

ऑल इंडिया स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब मंडी बोर्ड की ओर से चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट के नेतृत्व में आयोजित 'ऑल इंडिया स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 (सीजन-2)' का शुभारंभ हो गया। 7 से 12 जून तक चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की टीमों हिस्सा ले रही हैं।

टूर्नामेंट की शुरुआत से पूर्व किसान भवन, चंडीगढ़ में खिलाड़ियों और अधिकारियों के सम्मान में विशेष डिनर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने विभिन्न राज्यों से पहुंची टीमों का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा खिलाड़ियों को गुलदस्ते भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया।

अपने संबोधन में बरसट ने कहा कि खेल



युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा राज्य की मंडियों को ऑफ-सीजन के दौरान इनडोर स्टेडियम के रूप में विकसित कर युवाओं को निशुल्क खेल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मलोट, श्री मुक्तसर साहिब, सुल्तानपुर

लोधी और रामपुरा फूल मंडी में विभिन्न खेलों की मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट आपसी भाईचारे, टीम भावना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस दौरान मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में 700 प्रतिभागियों ने दिखाई ऊर्जा, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश



चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। खेल विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सेक्टर-42 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल' कार्यक्रम में लगभग 700 विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और साइकिलिंग को स्वस्थ एवं पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली के रूप में प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागियों द्वारा फिट इंडिया शपथ लेने के साथ हुई, जिसमें उन्होंने नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनाने और दूसरों को भी स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।

साइकिल रैली को खेल विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन के संयुक्त निदेशक खेल डॉ. महेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से साइकिलिंग को

दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में खेल विभाग के डॉ. भगवंत सिंह, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के खेल अधिकारी योगराज सिंह, फिट इंडिया मिशन की सलाहकार अंजलि तथा एसएआई की सहायक निदेशक पुष्कर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

इस आयोजन की विशेषता बड़ी संख्या में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की भागीदारी रही। उनकी सक्रिय उपस्थिति और उत्साह ने कार्यक्रम को और प्रेरणादायक बना दिया तथा फिट इंडिया अभियान की समावेशी भावना को मजबूत किया। पांच किलोमीटर लंबी साइकिल रैली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-42 से शुरू होकर सेक्टर 36-37/41-42 राउंडअबाउट, फर्नीचर मार्केट राउंडअबाउट, सेक्टर-43 बस स्टैंड चौक और अटावा चौक से होते हुए पुनः

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने 'पैडल फॉर हेल्थ, पैडल फॉर प्लेनेट' का संदेश देते हुए फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, पेयजल, जलपान और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। खेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेल विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों और सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन स्वस्थ, फिट और पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

6.58 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

चरणजीत सिंह चन्ना

जगराव/यूटर्न/7/जून। लुधियाना देहात पुलिस द्वारा साइगा की गई क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, थाना हट्टर के मुख्य अधिकारी एस.आई. गुर्सेवक सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ बस अड्डा, गाँव लक्खा के पास मौजूद थे। इस दौरान एक विशेष मुखबिर ने सूचना दी कि गाँव झोरड़ा के श्मशान घाट के पास एक व्यक्ति



कथित तौर पर हेरोइन के साथ मौजूद है। FIR के अनुसार, सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी

ने तुरंत रेड की। पुलिस के मुताबिक, गुरमीत सिंह उर्फ गैरी को काबू कर उसकी तलाशी ली गई। शिकायत के अनुसार, तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 6.58 ग्राम कथित हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने ठुडर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला जांच के अधीन है और पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है।

विशेष शिविरों में उमड़ा मतदाताओं का उत्साह, एक दिन में करीब 1 लाख मतदाताओं की हुई मैपिंग



चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन - एसआईआर) अभियान के तहत रविवार को राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के 24,453 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों को मतदाताओं का उत्साहजनक सहयोग मिला, जिसके चलते एक ही दिन में लगभग एक लाख मतदाताओं की सफलतापूर्वक मैपिंग की गई। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिदिता मित्रा ने इस उपलब्धि पर राज्य के मतदाताओं तथा बृथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार, रविवार को हुई कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में मतदाताओं की मैपिंग का आंकड़ा 85 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है, जो अभियान की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अनिदिता मित्रा ने बताया कि पंजाब में 25 जून से घर-घर जनगणना प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में मतदाताओं की सटीक जानकारी और रिकॉर्ड को अद्यतन रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे चुनाव आयोग के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने विवरणों की पुष्टि सुनिश्चित करें।

अब ₹2 सस्ता मिलेगा वेरका दूध, शुरू हुई मिल्क वेंडिंग मशीन सेवा



मोहाली/यूटर्न/07 जून। आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वेरका ने मोहाली में मिल्क वेंडिंग मशीन सेवा शुरू की है। इस नई पहल के तहत उपभोक्ताओं को वेरका दूध पैकेट वाले दूध की तुलना में प्रति लीटर ₹2 कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को अपने घर से साफ बर्तन लेकर आना होगा और आवश्यकता अनुसार सीधे मशीन से दूध प्राप्त करना होगा। वेरका अधिकारियों के अनुसार, वेंडिंग मशीन से मिलने वाला दूध उसी गुणवत्ता और मानकों का होगा, जो पैकेटबंद दूध में उपलब्ध कराया जाता है। कीमत में कमी का मुख्य कारण पैकेजिंग, प्लास्टिक पाउच और परिवहन लागत में होने वाली बचत है। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलने के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे में भी कमी आएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो भविष्य में मोहाली के अन्य क्षेत्रों और आसपास के शहरों में भी ऐसी वेंडिंग मशीनें स्थापित की जा सकती हैं। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन्हें सस्ता, ताजा और भरोसेमंद दूध मिलेगा, वहीं प्लास्टिक के उपयोग में कमी आने से पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा।





11 सोमवार, 08 जून 2026

पंजाब

यूटर्न टाइम

ऊपर से ठीक, अंदर से खोखली: आनंद विहार की सड़क बनी हादसे का खतरा

स्थानीय लोगों का दावा- किसी भी समय धंस सकती है इंटरलॉकिंग सड़क, नगर परिषद पर अनदेखी के आरोप

जीरकपुर/यूटर्न/07 जून। बलताना स्थित आनंद विहार की इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली सड़क इन दिनों क्षेत्रवासियों की चिंता का कारण बनी हुई है। बाहर से सामान्य दिखने वाली सड़क अंदर से खोखली हो चुकी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सड़क के नीचे की मिट्टी कई स्थानों पर बैठ चुकी है, जिससे किसी भी समय सड़क धंसने का खतरा बना हुआ है। निवासियों के अनुसार सड़क पर चलते समय कई जगह खालीपन महसूस होता है। उनका कहना है कि यदि किसी भारी वाहन, ट्रक या स्कूल बस का दबाव पड़ा तो सड़क अचानक धंस सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का आरोप है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन नगर



परिषद की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

आनंद विहार निवासी सुशील कुमार, रेखा, ममता, विकास और प्रदीप ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर परिषद अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया है। इसके बावजूद केवल आश्वासन ही मिले हैं। उनका कहना है कि

बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और बारिश के दौरान सड़क के नीचे की मिट्टी और कमजोर हो सकती है, जिससे खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तकनीकी जांच करवाई जाए और जहां-जहां खोखलापन है वहां तत्काल मरम्मत करवाई जाए। उनका कहना है कि किसी हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले ही समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गर्मी बढ़ते ही धधका ट्रांसफार्मर, बिजली व्यवस्था की तैयारियों पर उठे सवाल

मुबारकपुर-पंडवाला रोड पर ट्रांसफार्मर में लगी आग, बड़ा हादसा टला; ओवरलोडिंग और रखरखाव को लेकर चर्चा

डेराबस्सी/यूटर्न/07 जून। भीषण गर्मी के बीच बिजली की बढ़ती मांग के दौरान मुबारकपुर-पंडवाला रोड पर एक ट्रांसफार्मर में लगी आग ने क्षेत्र की बिजली व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के दौरान ट्रांसफार्मर से उठीं ऊंची लपटों और धुएँ के गुबार से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रांसफार्मर से पहले चिंगारियां निकलनी शुरू हुईं और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सड़क से गुजर रहे लोगों



और आसपास के दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर तुरंत दमकल विभाग और बिजली विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के दौरान कुछ

समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। राहत की बात यह रही कि आग आसपास की दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों तक नहीं पहुंची। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि गर्मी के मौसम में बढ़ते बिजली लोड को देखते हुए क्या ट्रांसफार्मरों की

नियमित जांच और रखरखाव किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय-समय पर निरीक्षण हो तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग से सभी ट्रांसफार्मरों का तकनीकी ऑडिट कराने और ओवरलोडिंग की समस्या का समाधान करने की मांग की है। हालांकि आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या अधिक लोड को संभावित वजह माना जा रहा है। घटना ने एक बार फिर गर्मी के मौसम में बिजली ढांचे की मजबूती और सुरक्षा उपायों को लेकर बहस छेड़ दी है।

निरंकारी मिशन ने रक्तदान शिविर लगाया

मिशन की भांखरपुर ब्रांच में 126 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ

डेराबस्सी/यूटर्न/07 जून। इंसानी रक्तदान कैम्पेनर को आगे बढ़ाते हुए, आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की रहनुमाई में संत निरंकारी सत्संग भवन, भांखरपुर में ब्लड डोनेशन कैम्प लगाया गया। कैम्प के दौरान, चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित गवर्नमेंट मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की डॉ. नितिका की लीडरशिप में 16 सदस्यी टीम ने अपने अनुभवी डॉक्टरों और स्टाफ की मदद से कुल 126 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का प्रोसेस पूरा किया। कैम्प में संगत और सेवादारों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और डेडिकेशन और बिना स्वार्थ के सेवा की भावना दिखाई।



इस कैम्प को सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि प्यार, मेलजोल और बिना स्वार्थ के सेवा की जीती-जागती मिसाल बताया। उन्होंने बताया कि संत निरंकारी मिशन 1986 से लगातार ब्लड डोनेशन कैम्पेन के जरिए इंसानियत की सेवा में लगा हुआ है। अब तक देश भर में 9,174 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैम्प के जरिए

लगभग 15 लाख यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है, जो इसे देश के सबसे बड़े वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैम्प कैम्पेन में से एक बनाता है। इस मौके पर भांखरपुर ब्रांच के मुखी गुरदास ओबराय जी ने कहा कि युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने संगत को सच्चाई, सादगी और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और युवाओं को नशा-मुक्त जीवन अपनाकर समाज सेवा की ओर आगे बढ़ने का संदेश दिया। बाबा हरदेव सिंह जी ने हृदय नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए का संदेश दिया और सेवा को जीवन का अहम हिस्सा बनाया, जिसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इस मौके पर ब्रांच मुखी ने आस-पास की ब्रांचों के मुखी महात्माओं, क्षेत्रिय संचालक राजेश गौड़ जी, इलाके के गणमान्य व्यक्तियों, ब्लड डोनेर्स, डॉक्टरों, सेवादारों और संगत का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिनके सहयोग और सपोर्ट से यह कैम्प सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

घर में घुसकर परिवार पर हमला, महिला से बदसलूकी के आरोप; 10 लोगों पर केस

डेराबस्सी/यूटर्न/07 जून। निकटवर्ती गांव मीरपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और महिला से कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एसएसआई लखविंदर सिंह के अनुसार गांव मीरपुर निवासी छिंदा पुत्र श्याम लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तीन जून की रात करीब साढ़े दस बजे वह अपने घर पर मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।

शिकायतकर्ता के अनुसार शोर सुनकर उसके पिता श्याम लाल और पत्नी प्रीति भी बाहर आ गए। उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने प्रीति के साथ अशोभनीय व्यवहार किया और खींचतान के दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए। परिवार के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकियां देते हुए वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर सतपाल, अजय, विजय, सिबू, राकेश, अशोक, सिमी, कमल, शुभम और सुमित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शरवरी वाघ का बोल्ड अवतार चर्चा में, सोशल मीडिया पर बड़ी फैस की धड़कनें



शरवरी वाघ

मुंबई/यूटर्न/07 जून। बॉलीवुड अभिनेत्री शरवरी वाघ एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सामने आई उनकी नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। तस्वीरों में शरवरी का स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक फैस को खूब पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में उनके फैशन सेंस और फिटनेस की जमकर तारीफ की जा रही है। फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि शरवरी लगातार अपने बोल्ड और ट्रेंडी फोटोशूट्स के जरिए युवा दर्शकों के बीच लोकप्रियता बढ़ा रही हैं। उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।



पंजाब के 8 नगर निगमों में मेयर चुनाव की तैयारी तेज, राजनीतिक दलों ने शुरू की जोड़तोड़

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब के आठ नगर निगमों में मेयर चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से आवश्यक अधिसूचनाएं जारी होने के बाद राजनीतिक दलों ने नगर निगमों में सत्ता हासिल करने के लिए अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। आगामी चुनाव अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, कपूरथला, मोगा, पटियाला और मोहाली नगर निगमों में कराए जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार, मेयर पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। चुनाव के लिए विशेष बैठकें बुलाई जाएंगी, जिनमें पार्षद मेयर के चुनाव में



हिस्सा लेंगे। चुनावी प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सबसे पहले उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होंगे और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर मतदान कराया जाएगा। यदि किसी नगर निगम में केवल एक ही उम्मीदवार मैदान में रहता है तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। नगर निगमों में मेयर

चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रमुख दल अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने और बहुमत सुनिश्चित करने में जुट गए हैं। कई नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत की स्थिति नहीं होने के कारण निर्दलीय और छोटे दलों के पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नियमों के अनुसार मतदान में केवल निर्वाचित पार्षद ही भाग ले सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया का

संचालन निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत किया जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में गणपूर्ति (क्वोरम) का विशेष महत्व रहेगा। यदि निर्धारित संख्या में पार्षद उपस्थित नहीं होते हैं तो बैठक स्थगित की जा सकती है और नियमों के अनुसार दोबारा बैठक बुलाकर चुनाव कराया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मेयर चुनाव केवल स्थानीय निकायों की सत्ता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की ताकत और आगामी राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी देंगे। इसलिए सभी प्रमुख दल इन चुनावों को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं।

हम पर भरोसा करें, लेकिन E20 पेट्रोल के बारे में सवाल न पूछें

भारत में E20 पेट्रोल का बदलाव एक दिलचस्प पड़ाव पर पहुँच गया है। सरकार चाहती है कि नागरिक इस पॉलिसी के पीछे के विज्ञान पर भरोसा करें। वह बस यह नहीं चाहती कि वे उस विज्ञान को देखें। सालों से गाड़ी मालिकों से कहा जा रहा है कि वे चिंता न करें। हमें भरोसा दिलाया गया कि E20 पेट्रोल पर एक्सपर्ट्स ने बहुत रिसर्च की है। माइलेज कम होने, इंजन खराब होने, जंग लगने और कम्पैटिबिलिटी (गाड़ी के साथ तालमेल) जैसी चिंताओं की बारीकी से जाँच की गई है। किसानों को फायदा होगा, तेल का आयात कम होगा और देश एक हरियाली भरे भविष्य की ओर बढ़ेगा। इसमें सबकी जीत है।

तभी एक मुश्किल सवाल सामने आया।

मुंबई के एक नागरिक ने RTI के जरिए उन स्टडीज की जानकारी माँगी जिनका ज़िक्र सरकार ने खुद E20 को लागू करने के समर्थन में किया था। यह कोई क्रांतिकारी माँग नहीं थी। न ही यह कोई मिलिट्री सीक्रेट जानने की अपील थी। बस रिपोर्ट चाहिए थीं। जवाब क्या मिला? माफ कीजिए, यह गोपनीय है।

जाहिर है, जो रिसर्च यह साबित करती है कि E20 लाखों गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, वह उन लाखों गाड़ी मालिकों के लिए बहुत संवेदनशील है जो इसका इस्तेमाल करेंगे। नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वे फ्यूल का इस्तेमाल करें, उसके पैसे दें और उसके नतीजों को झेलें—लेकिन उस फ्यूल के बारे में स्टडीज न पढ़ें।

इससे गर्वनेस का एक दिलचस्प नया पैमाना बनता है। इससे उस स्कूल टीचर की याद आती है जो कहता है कि किसी स्टूडेंट को मैथ में पूरे नंबर मिले हैं, लेकिन वह आंसर शीट दिखाने से मना कर देता है क्योंकि उसमें कुछ खास कैलकुलेशन हैं।

विडंबना साफ है। अगर स्टडीज पक्के तौर पर यह साबित करती हैं कि E20 सुरक्षित और फायदेमंद है, तो उन्हें जारी करने से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अगर कुछ हिस्सों में कमर्शियल तौर पर संवेदनशील जानकारी है, तो उन हिस्सों को छिपाया जा सकता है। दुनिया भर की सरकारें असली ट्रेड सीक्रेट्स को सुरक्षित रखते हुए अक्सर रिसर्च की समरी पब्लिश करती हैं।

इसके बजाय, जनता से एक नई फ्यूल पॉलिसी अपनाने के लिए कहा जा रहा है जो रैवज्ञानिक भरोसे के सिद्धांत पर आधारित है।

एक्सपर्ट्स पर भरोसा करें। डेटा न माँगें।

टेस्टिंग पर भरोसा करें। नतीजे न माँगें।

नतीजों पर भरोसा करें। यह न पूछें कि वे कैसे निकले।

RTI एक्ट के तहत जानकारी देने से मना करना कानूनी तौर पर सही हो सकता है। लेकिन कानूनी होना और समझदारी दिखाना हमेशा एक ही बात नहीं होती। देश की लगभग हर पेट्रोल गाड़ी पर असर डालने वाली पॉलिसी किसी जादूगर के करतब जैसी नहीं होनी चाहिए, जहाँ दर्शकों को बार-बार बताया जाता है कि ट्रिक पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उन्हें कभी पर्दे के पीछे नहीं देखना चाहिए। आखिरकार, सरकारों को एक साधारण नियम याद रखना चाहिए: अगर नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी गाड़ियाँ E20 पर चलाएँ, तो उनसे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे अपना दिमाग आँख बंद करके किए गए भरोसे पर चलाएँ।



संदीप शर्मा, सम्पादक

पंजाब भाजपा के महासचिव पद से डॉ. जगमोहन राजू का इस्तीफा, जनहित मुद्दों पर फोकस करने की कही बात

चंडीगढ़/यूटर्न/07 जून। पंजाब भाजपा में संगठनात्मक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संगठन महामंत्री मंथरी श्रीनिवासूल को पत्र लिखकर संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार, इस्तीफे की प्रति प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह दिल्ली को भी भेजी गई है। अपने पत्र में डॉ. राजू ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान उन्हें पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाने का अवसर मिला और यह समय उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय रहा। डॉ. राजू ने स्पष्ट किया कि अब वह पंजाब और देश से जुड़े कई सामाजिक एवं जनहित के मुद्दों पर अधिक सक्रियता से काम करना चाहते



हैं। उन्होंने अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा दिलाने, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की शिक्षा, शिक्षा के अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुसूचित जातियों और सिख समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा, नशा विरोधी अभियान, धर्मांतरण, पंजाबी भाषा के संरक्षण तथा पंजाब से जुड़े जल और चंडीगढ़ जैसे लंबित विषयों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर व्यापक अध्ययन, जनसंपर्क, कानूनी प्रयास और जागरूकता

अभियानों की आवश्यकता है। ऐसे में संगठन में महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए इन विषयों को पर्याप्त समय देना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। राजनीतिक हलकों में डॉ. राजू का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पंजाब भाजपा में संगठनात्मक बदलाव और नेतृत्व को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में किसी प्रकार की नाराजगी का उल्लेख नहीं किया है और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में जनहित के मुद्दों पर कार्य जारी रखने की बात कही है। पार्टी की ओर से फिलहाल उनके इस्तीफे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इसे पंजाब भाजपा के भीतर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक घटनाक्रम माना जा रहा है।

मोबाइल छीनने के शक में दो दलित युवकों को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, पेड़ से बांधकर किया अमानवीय व्यवहार

मुक्तसर/यूटर्न/07 जून। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांव झोरड़ में कथित मोबाइल फोन छीनने के आरोप में दो दलित युवकों के साथ भीड़ द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल है। जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लोगों ने दो युवकों पर एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगाया।

आरोप है कि इसके बाद भीड़ ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी बेरहमी से पीटाई की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवकों के कपड़े फाड़कर उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया तथा रस्सियों से बांधकर खेतों में घसीटा गया। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें एक पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस

ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।